**ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA**
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
**PP. No.- 186-188**
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-17, No.- I, Issues-31, YEAR- Jan.-March-2024

# उच्च शिक्षित बेरोजगारी की समस्याः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

मंगल चन्द राय
शोध अध्येता– असिस्टेन्ट प्रोफेसर– समाजशास्त्र विभाग, श्री मुरली मनोहर टाऊन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया (उ0प्र0) भारत

**Received-18.03.2024, Revised-25.03.2024, Accepted-30.03.2024** **E-mail: mangalrai1980@gmail.com**

***सारांशः** प्रत्येक राष्ट्र के लिए युवा वह मानव संसाधन है, जिस पर उस देश का सर्वांगीण विकास निर्भर करता है। किसी भी राष्ट्र के सम्पूर्ण विकास के लिए यह अति आवश्यक है कि युवा रूपी मानव संसाधन का उचित रूप से प्रयोग किया जाए, इसमें विशेषकर उच्च शिक्षित युवा वर्ग का, क्योंकि एक तरफ जहाँ उसके पास योग्यता अधिक होती है, वहीं दूसरी तरफ उसके विचार और आकांक्षाएं अपने और राष्ट्र के प्रति सकारात्मक होता है, जो कि एक राष्ट्र के सम्पूर्ण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।*

*यह तभी संभव है जब राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक मुख्य धारा में शिक्षित युवा वर्ग पूर्ण आत्मविश्वास और पूर्ण मनोयोग से अपनी क्षमता का शत–प्रतिशत प्रयोग करे। वर्तमान में भारत ऐसे विकासशील देश में यह देखा जा रहा है कि उच्च शिक्षित बेरोजगारी की समस्या गम्भीर रूप लेती जा रही है और भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र होते हुए भी अपने युवा संसाधनों का अपने विकास में उपयोग नहीं कर पा रहा, क्योंकि वह अपने युवाओं को क्षमता के अनुसार रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है।*

*राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन, इंस्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेन्ट आदि संगठनों के रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वर्तमान में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या एक गम्भीर रूप ग्रहण कर ली है। यद्यपि शासन व्यवस्था इस समस्या के समाधान के लिए कई कार्यक्रम प्रारम्भ किया है, परन्तु इसका बहुत व्यापक प्रभाव नहीं देखा जा रहा है। हम अपने शोध लेख में उच्च शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को समाजशास्त्रीय आधार पर समझने का प्रयास करेंगे।*

***कुंजीभूत शब्द–** युवा, उच्च शिक्षित बेरोजगारी, राष्ट्र, समस्या, विकासशील, सर्वांगीण विकास, संसाधन, शिक्षित युवा वर्ग, योग्यता।*

वर्तमान भारतीय सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था में बेरोजगारी, विशेषकर उच्च शिक्षित बेरोजगारी की समस्या जटिल रूप धारण करती जा रही है। इस सामाजिक–आर्थिक समस्या का भयावह रूप अल्प विकसित व विकासशील देशों में तो है ही, विकसित देशों में भी यह समस्या किसी न किसी रूप में विद्यमान है। भारत ऐसे देश में जहाँ जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है, वहाँ यह स्थिति दिन–प्रतिदिन गम्भीर होती जा रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इण्डिया इकोनोमी के अनुसार जून 2023 में भारत में बेरोजगारी दर 8.45 प्रतिशत तक पहुँच गई, जब कि मई 2023 में यह 7.68 प्रतिशत थी। उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवाओं की स्थिति और दयनीय है। इंस्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेन्ट के अनुसार 2022–23 तक 25 प्रतिशत स्नातक नौकरी पाने में असफल रहे हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के आकड़ों के अनुसार, अक्टूबर–नवम्बर 2020 में बेरोजगारी की दर 10.3 प्रतिशत थी, जो पिछले वर्ष 2019 में 7.9 प्रतिशत से अधिक थी।

वर्तमान भारतीय समाज में बेरोजगारी की तरह एक अभिशाप है। यह समस्या अतिशय जनसंख्या वृद्धि, सरकार की गलत आर्थिक नीतियों, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, कम्प्यूटरीकरण का अतिशय प्रसार, कौशल शिक्षा की कमी आदि के कारण दिन–प्रतिदिन विकराल रूप धारण करती जा रही है। बेरोजगारी जहाँ एक तरफ युवा के आत्मविश्वास को कम करती है, वहीं दूसरी तरफ उसके अंदर हीनता की भावना को भी जन्म देती है। यह एक ऐसी सामाजिक–आर्थिक समस्या है जो अन्य सामाजिक–आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। आगबर्न एवं निमकॉफ ने बेरोजगारी पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि बेरोजगारी आधुनिक युग की अत्यधिक गम्भीर सामाजिक समस्याओं में से एक है, यह सामाजिक विघटन का प्रमाण है।

बेरोजगारी अपने आप में जहाँ व्यक्ति के लिए अभिशाप है, वहीं सामाजिक व्यवस्था के लिए भी बहुत ही नकारात्मक है। यह सीधे गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, अपराध और शिक्षा से अर्न्तसम्बन्धित है। व्यापक बेरोजगारी की स्थिति राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुँचाती है, जिससे राष्ट्र की आर्थिक गतिशीलता धीमी पड़ती है।

**बेरोजगारी क्या है?–** बेरोजगारी शब्द का तात्पर्य व्यक्ति की उस स्थिति से है, जिसमें व्यक्ति के कार्य करने की इच्छा एवं सामर्थ्य रहते हुए भी कार्य नहीं मिल पाता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बेरोजगारी को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि एक सामान्य कार्यबल के सदस्य (15 से 59 वर्ष) का सामान्य कार्यकाल में सामान्य वेतन पर और उसकी इच्छा के विरूद्ध वैतनिक कार्य से अलग रखना बेरोजगारी है।

डि. मैलो (1969: 24) ने बेरोजगारी को परिभाषित करते हुए कहा है, ''यह वह परिस्थिति है जिसमें एक व्यक्ति इच्छा के बावजूद वैतनिक रूप से सम्बन्धित नहीं होता है।''

जी.आर. मदान ने लिखा है कि ''बेरोजगारी एक स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति को मजदूरी के सामान्य स्तर पर काम नहीं मिलना है, जो काम करना चाहता है।''

फ्लोरेंस ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि, ''बेरोजगारी उसकी निष्क्रियता के रूप में परिभाषित की जा सकती है जो कार्य करने के योग्य और इच्छुक है।''

अतः स्पष्ट है कि बेरोजगारी के तीन प्रमुख तत्व हैं :

1. व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए।
2. व्यक्ति में कार्य करने की इच्छा होनी चाहिए।

**अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक**

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-17, No.- I, Issues-31, YEAR- Jan.-March-2024

3. व्यक्ति को काम ढूढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए।

इससे स्पष्ट है कि कोई योग्य यदि जान–बूझकर रोजगार नहीं करना चाहता तो उसे बेरोजगार नहीं कहा जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति भिक्षावृत्ति करता है तो भी उसे बेरोजगार नहीं कहा जायेगा।

विभिन्न देशों में बेरोजगारी के स्वरूप में पर्याप्त भिन्नता पायी जाती है। विकासशील एवं अल्प विकसित देशों में बेरोजगारी का स्वरूप संरचनात्मक प्रकार का है। यहाँ बेरोजगारी पिछड़े हुए आर्थिक ढ़ांचे से सम्बन्धित है, इसी कारण यहाँ बेरोजगारी का स्वरूप स्थाई एवं दीर्घकालीन प्रवृत्ति की है। इन देशों में रोजगार की इच्छा रखने वाले की तुलना में रोजगार की उपलब्धता कम है। पूंजी निर्माण की दर नीचे होने से आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी है। इसी कारण रोजगार सृजन रोजगार चाहने वालों की तुलना में बहुत कम है। इसके ठीक विपरीत विकसित देशों में बेरोजगारी का स्वरूप एकदम भिन्न है। यहाँ बेरोजगारी का प्रमुख कारण मांग में कमी है। इसी वजह से विकसित देशों में बेरोजगारी अस्थाई एवं अल्पकालीन है।

**बेरोजगारी के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं :**

मौसमी बेरोजगारी– मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र एवं कुछ विशेष उत्पादक इकाईयों जैसे– चीनी एवं बर्फ उद्योग में देखने को मिलती हैं, क्योंकि इसमें श्रमिक को वर्ष में 6 महीने बेकार बैठना पड़ता है।

**प्रच्छन्न बेरोजगारी (छिपी बेरोजगारी)** – छिपी बेरोजगारी के अन्तर्गत आवश्यकता से अधिक लोग एक ही कार्य का सम्पादन करते हुए देखे जाते हैं। यदि अतिरिक्त लोगों को काम से हटा लिया जाए तो उत्पादन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र के कृषि क्षेत्र में देखी जा सकती है।

**अल्प बेरोजगारी–** इसके अन्तर्गत श्रमिक को थोड़ा–बहुत काम मिलता है, वह पूरी क्षमता के अनुसार अपना काम नहीं कर पाता है।

**खुली बेरोजगारी–** खुली बेरोजगारी वह स्थिति है, जिसमें यद्यपि श्रमिक काम करने के लिए तैयार होता है तथा उसमें काम करने की योग्यता भी होती है, परन्तु उसे काम नहीं मिलता है।

**चक्रीय बेरोजगारी–** चक्रीय बेरोजगारी व्यापार और व्यवसाय में उतार–चढ़ाव आने के कारण होता है। इससे श्रमिक के हितों को नुकसान पहुँचता है।

**संरचनात्मक बेरोजगारी–** संरचनात्मक बेरोजगारी मूल रूप से आर्थिक ढ़ांचे से सम्बन्धित है। जब आर्थिक ढ़ांचे में परिवर्तन होता है तो इस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है।

**शैक्षिक बेरोजगारी–** शिक्षित लोगों में पायी जाने वाली बेरोजगारी को शैक्षिक बेरोजगारी कहते हैं। इसके अन्तर्गत या तो शिक्षित को उसकी योग्यता के हिसाब से रोजगार नहीं मिलता या फिर उसे किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिलता।

हम यहाँ पर शैक्षिक बेरोजगारी को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। भारत में शिक्षित बेरोजगारी, विशेषकर उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगारी की समस्या गम्भीर रूप ग्रहण कर ली है। शिक्षित लोग दो प्रकार के होते हैं– एक वे जो कार्य कुशल शिक्षित होते हैं, जो किसी न किसी प्रकार की तकनीकी शिक्षा ग्रहण किये होते हैं और दूसरे वह शिक्षित होते हैं, जो अकार्य कुशल होते हैं और सिर्फ सामान्य रूप से विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण किये हुए होते हैं। कार्य कुशल शिक्षित लोगों के सामने रोजगार की कमी नहीं है, भले ही वे अल्प रोजगार ही क्यों न प्राप्त किये हों। सबसे गम्भीर समस्या महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त युवाओं के सामने है क्योंकि उनकी शिक्षा जीविका से सम्बन्धित नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने वार्षिक प्रतिवेदनों में इस तथ्य को उद्घाटित किया है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली गतिहीनता उत्पन्न करती है, यह सिर्फ शिक्षित बनाती है न कि कार्य कुशल। इससे बेरोजगारों की फौज खड़ी होती जा रही है। कोठारी कमीशन (64–66) ने अपने प्रतिवेदनों में स्वीकार किया है कि वर्तमान शिक्षा के विषयों और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों के बीच एक चौड़ी खाई विद्यमान है।

मजूमदार ने (2013) अपने अध्ययन में पाया कि भारतीय स्नातकों एवं परास्नातकों में 11 प्रतिशत से भी अधिक रोजगारविहीन हैं। इसी के साथ–साथ तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं की स्थिति भी रोजगार के क्षेत्र में चिन्ताजनक है। तकनीकी शिक्षा प्राप्त 13 प्रतिशत छात्रों के पास किसी प्रकार का रोजगार नहीं है।

एन.एस.एस.ओ. की एक रिपोर्ट के अनुसार मामूली कुशल युवाओं के बीच बेरोजगारी लगभग 27 प्रतिशत तथा अधिक कुशल युवाओं में यह लगभग 20 प्रतिशत है। पुरूषों के तुलना में महिलाओं के बीच कुशलता युक्त बेरोजगारी के मामले अधिक देखे गये हैं क्योंकि बहुत सी तकनीकी शिक्षा प्राप्त महिलाएं विवाह के उपरान्त रोजगार चाहते हुए भी रोजगार नहीं कर पाती हैं।

ब्लूमबर्ग के नवीनतम अध्ययन में सेंटर फॉर मानिटरिंग इंडियन इकोनोमी के जुलाई के अंक में यह संदर्भ दिया गया है कि भारत में कुल शिक्षित बेरोजगारी 7.9 प्रतिशत रही है। जो प्रतिवर्ष लगातार बढ़ रही है।

चर्चा से स्पष्ट है कि भारत जैसे विकासशील देश में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या दिन–प्रतिदिन विकराल रूप ग्रहण करती जा रही है। इसमें भी उच्च शिक्षित बेरोजगारी की स्थिति और दयनीय है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश में बड़े पैमाने पर शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई, जिससे बड़े पैमाने पर डिग्रीधारी युवा रोजगार के लिए तैयार हुए। परन्तु इन युवाओं को किसी प्रकार की कौशल शिक्षा प्रदान नहीं की गई थी, जिस कारण उनकी शिक्षा का कोई व्यवसायिक उपयोग नहीं था। देश की शिक्षा प्रणाली भी दोषपूर्ण थी जो लम्बे समय तक मैकाले की शिक्षा नीति पर निर्भर थी जो भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ लिपिक वर्ग को तैयार कर रही थी। जिसकी राष्ट्र के उत्पादकता में कोई योगदान नहीं था। देश की जनसंख्या में भी तीव्र गति से वृद्धि होने के कारण पर्याप्त मात्रा में रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाया। साथ ही साथ आर्थिक संरचना भी कम उत्पादक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-17, No.- I, Issues-31, YEAR- Jan.-March-2024

थी और गरीबी होने के कारण मांग की कमी थी, जिससे रोजगारसृजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में बेरोजगारी की दर गुणात्मक रूप से बढ़ने लगी।

शिक्षित बेरोजगारी के परिणामस्वरूप शिक्षित युवाओं में मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। बेरोजगारी की स्थिति में जब युवा अपनी इच्छाओं और अपने परिवार की आशाओं एवं आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता तो वह हीनताबोध का शिकार हो जाता है। ऐसे युवा निराशा, कुण्ठा में डूब जाते हैं और इनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। ऐसी मनोदशा से ग्रस्त युवाओं का व्यक्तित्व का विघटन तो होता है साथ ही साथ सामाजिक विघटन की भी प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। आर्थिक आवश्यकता जहाँ ऐसे हताश युवाओं को आर्थिक अपराध के लिए प्रेरित करती है वहीं निराशा और कुण्ठा से भी युवा अपराध की ओर अग्रसर होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो युवा देश के निर्माण के लिए आधार होते हैं वही राष्ट्र के विध्वंस के कारक बन जाते हैं।

विगत कुछ वर्षों से शिक्षित बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने कौशल आधारित ज्ञान देने पर बल दिया तथा बड़े पैमाने पर मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा कोर्सेज प्रारम्भ किये ताकि युवा आत्मनिर्भर बन सके। सरकार ने युवाओं में कौशल बढ़ाने के लिए नयी शिक्षा नीति 2020 को लागू कर इस क्षेत्र में एक नया प्रयास किया है। सरकार ने युवाओं के लिए "स्टार्टअप" शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी है ताकि वे अपने उत्पादों को बाजार में उपलब्ध करवा सके।

यद्यपि सरकार ने इस क्षेत्र में काफी प्रयास किया है, परन्तु इस दिशा में यदि निम्न प्रयास किये जायेंगे तो इस समस्या के समाधान में लाभकारी होगा :

– सर्वप्रथम इस बात की आवश्यकता है कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाए। इंदिरा गांधी ने एक बार टिप्पणी करते हुए कहा था कि अतिशय जनसंख्या वृद्धि विकास को इस प्रकार से नष्ट कर देती है, जिस प्रकार से समुद्र की एक लहर समुद्र के किनारे बने हुए रेत के ढ़ांचे को।

– शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है। इसे अधिक से अधिक कुशल पूर्ण बनाते हुए रोजगार उत्पादन के रूप में बनाना होगा।

– ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि को व्यवसायिक रूप प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि शिक्षित युवा उसे विकल्प के रूप में अपना सके।

– लघु और कुटीर उद्योगों को स्टार्टअप के माध्यम से जोड़ना होगा, जिससे उनमें नयी ज्ञान व कौशल के साथ–साथ बाजार भी मिल सके।

– शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य सरकारी नौकरी पाना, इस मनोदशा को भी बदलने की आवश्यकता है तॉकि युवा अपने जीवन के स्वर्णिम काल को सरकारी नौकरी खोजने में व्यर्थ न कर दे।

– शिक्षा व्यवस्था में एक फिल्टरेशन की भी व्यवस्था करनी होगी, तॉकि समय से यह पता चल सके कि युवाओं का रूझान किस दिशा में है ताकि उनको उसी क्षेत्र में पारंगत किया जा सके।

**निष्कर्ष–** उपर्युक्त चर्चा से स्पष्ट है कि वर्तमान समय में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या दिन–प्रतिदिन गम्भीर स्वरूप ग्रहण करती जा रही है तथा शिक्षा प्रणाली में निहित कमियो के कारण वर्तमान संदर्भ में कोई स्पष्ट समाधान नहीं दिख रहा है क्योंकि जनसंख्या की अतिशय वृद्धि से सभी कार्यक्रम उतने सफल नहीं हो पा रहे हैं, जितना होना चाहिए। यद्यपि विगत कुछ वर्षों से परम्परागत ज्ञान आधारित शिक्षा प्रणाली को कौशल आधारित ज्ञान प्रणाली में परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। आशा किया जाना चाहिए कि भविष्य में सरकार द्वारा उठाये गये कदम फलदायी होंगे तथा उच्च शिक्षित बेरोजगारी की समस्या का उचित समाधान हो सकेगा।

## संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. पाण्डेय, तेजेस्कर और पाण्डेय संगीता (2016), भारत में सामाजिक समस्याएं, मैग्रा हिल एजुकेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
2. सिंह, गोपीरमण प्रसाद (2014), भारत में सामाजिक व्याधिकी, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।
3. आहूजा, राम (2016), सामाजिक समस्याएं, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
4. शर्मा, जी.एल. (2015), सामाजिक मुद्दे, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।

*****